Speaking at Press Conference, Dehradun, Uttarakhand

February 07, 2017

लेकिन केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास के हमारे नारे को कार्यान्वत किया, हर प्रदेश के साथ बिना भेदभाव के कार्य किया | और जब उत्तराखंड में हमारे लोग कहते थे कि यहाँ बिजली कभी आती है, जाती है, तकलीफ आती है तो लगभग 17% अधिक बिजली केंद्र सरकार ने देके यहाँ सुनिश्चित किया कि बिजली की कमी ना हो | और आज भी परिस्थिति ऐसी है कि जब उत्तराखंड चाहे, जितनी बिजली चाहे उतनी हमने पॉवर एक्सचेंज में उपलब्ध कराके सुनिश्चित किया है कि चौबीसों घंटे पूरे देश में बिजली दी जा सके |

मैं मोबाइल फ़ोन कोई फ़ोन लेने के लिए नहीं खोल रहा हूँ | हमारे मोबाइल अप्प के माध्यम से हम आप सबको भी जानकारियां देते हैं, पूरे चौबीस घंटे आपको जानकारियां उपलब्ध है कि कितनी बिजली पॉवर एक्सचेंज में उपलब्ध है, कितनी बिजली उत्तराखंड खरीद सकता है | और आपको जानके ख़ुशी होगी, इस वक़्त जब मैं आपको सम्भोदन कर रहा हूँ, अब समय हुआ है 1.56 आपकी घडी में देख लें, इस वक़्त पॉवर एक्सचेंज में मात्र 2.70 रुपये में, मात्र 2.70 रुपये में बिजली उपलब्ध है उत्तराखंड को खरीदने के लिए | और, अगर जानकारियों को और देखें तो उत्तराखंड भी अभी के समय लगभग 2000 MW power exchange में available है, पूरे उत्तराखंड की demand मात्र 1300-1400 MW है | अभी के समय demand 1350 MW है |

पर दुर्भाग्य की बात यह कि राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में ऊर्जा का विकास नहीं किया, आज भी लगभग 411 MW उनको power exchange से लेना पड़ रहा है |

वह प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिसने power exchange में कहाँ यह देश power shortage से लिप्त हुआ था आज पूरा देश power surplus बन गया है, कोयला surplus बन गया है | और किधर भी बिजली और कोयले की कमी नहीं है और उसी के कारण उत्तराखंड भी 411 MW मात्र ढाई-तीन रुपये में खरीद पा रहा है जिसके कारण आज प्रदेश में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है | तो कोई भ्रमित न हो कि राज्य सरकार ने कोई नयी योजनायें चालू कीं या नए ऊर्जा के कारखाने चाहे वह कोयले के हों, चाहे हाइड्रो हों उसपे कोई बल दिया हो | राज्य सरकार तो भ्रष्टाचार में लिप्त रही विकास के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है | वह तो केंद्र सरकार ने इतनी बिजली उपलब्ध करा दी, सस्ती बिजली, टिकाऊ बिजली जिसके कारण आज राज्य में लोगों को बिजली मिल पा रही है | और जो सालों साल के आंकड़े हैं मेरे पास, छोड़के जा सकता हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट हो, उस परिस्थिति को बदल के आज केंद्र ने इसको power surplus बना दिया है |

मैं दो-तीन और विषय रखना चाहूँगा आपके सामने | एक One rank-One pension का विषय, बहुत संवेदना का विषय है जिसमें पूरे देश में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे army, navy, air force के सेनानियों को बहुत पीड़ा उठानी पड़ी, कई वर्षों की इनकी डिमांड रही | मैं आपको उसकी chronology थोडा सा बताना चाहूँगा, डिमांड तो कई वर्षों की थी | श्रीमती सोनिया गाँधी जी ने 23 नवम्बर, 2002 को एक चंडीगढ़ में रैली सम्भोदित करते हुए यह ऐलान किया था कि One rank-One pension होना चाहिए, 2002 में माननीय सोनिया गाँधी जी ने, कांग्रेस अध्यक्षा ने | 2004 के कांग्रेस के manifesto में कहा गया और मैं quote करता हूँ - The long pending issue of One rank, One pension, will once again be re-examined and the satisfactory solution arrived at expeditiously. 2004 के घोषणा पत्र में |

जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, Presidential address, उस अभिभाषण में जून 2004 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई announce किया और मैं quote करता हूँ - The welfare of ex-servicemen will get priority and they will be involved in crucial nation building tasks.

2008 में, 4 वर्ष हो गए थे कांग्रेस की सरकार को, 2008 में उस समय के Defense Minister AK Antony साहब ने एक लिखित जवाब में राज्य सभा को दिसम्बर 11, 2008 को बताया कि government ने One rank, One pension की डिमांड को acceptable नहीं पाया, स्वीकृत नहीं किया | और मैं quote करता हूँ - The government has not found acceptable the demand for One rank, One pension (OROP) by the ex-servicemen, 2008 में.

फिर 2014 में, पूरे 10 वर्ष बाद, उनकी सरकार को 10 वर्ष हो गए थे जब ध्यान आया कि पूरे देश में सभी ex-servicemen उनके खिलाफ जा रहे हैं, उत्तराखंड में बहुत उत्तेजना थी उस समय और उत्तराखंड के हमारे वीरों ने, कई वीरों ने सेवा भी की है हमारी army, air force और naval forces में और अपने जान और प्राण भी दिए हैं इस देश के खातिर | उन सबकी पीड़ा को जब उन्होंने समझा, 10 वर्ष लग गए समझने में, तो 2014 में UPA-2 के समय, उस समय की कांग्रेस सरकार ने announce किया कि अब हम implement करेंगे OROP | जब एकदम स्पष्ट हो गया था कि इस सरकार का समय आ गया है, चुनाव सर पर था आने वाला था कुछ ही महीनों में, चुनाव की घोषणा लगभग तय थी | तब कांग्रेस जागी 10 वर्ष बाद और अब देखिये कैसे भ्रमित किया हमारे सेनानियों को, हमारे ex-servicemen को, OROP का Interim Budget 2014-15 में घोषणा करते हुए मात्र 500 करोड़ रुपये की provision की, मात्र 500 करोड़ रुपये |

मैं समझता हूँ यह उनकी बेईमानी थी कि उन्होंने 10 वर्ष लगा दिए एक घोषणा करने के बाद 2004 में और 10 वर्ष तक एक रुपया नहीं दिया OROP के लिए | और 2014 के Interim Budget जब जो एक vote-on-account के रूप में होता है, जाती हुई सरकार और तब तक तो पूरे देश में अनुमान लग गया था कि इस सरकार के वापिस आने का कोई संभावना नहीं है | और जनता ने मात्र 44 MP भेजे कांग्रेस के, 20% लोग भी कांग्रेस के चुनके नहीं आ पाए, क्यों? क्योंकि जनता ने इनके फरेब को भली-भांति समझ लिया था | मात्र 500 करोड़ रुपये क्या OROP कर सकता था? प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदनाशील प्रयत्नों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने OROP की मांग को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया लेकिन 11-12,000 करोड़ रुपये का उसका जो cost है उसको स्वीकार किया और लगभग दो किश्तों में 6000 से अधिक करोड़ रुपये बाँट चुके हैं और बाकी भी किश्तों में बाँटा जा रहा है और फिर आगे वाले वर्षों में regular OROP के तहत नए pension आवंटन किये जायेंगे |

मैं समझता हूँ इससे स्पष्ट होता है कि कौन सी सरकार ईमानदारी से हर एक ex-servicemen की सेवा करना चाहती थी और कांग्रेस कैसे भ्रमित रखा लोगों को 10 वर्षों तक, और जाते जाते भी जो करके गए वह एक प्रकार से मेरे हिसाब से बहुत ही छल था हमारे वीर सेनानियों के साथ | मैं हमारे सेनानियों को, हमारे वीर जवानों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इन सब मुश्किलों के बावजूद देश के खातिर जब ज़रूरत पड़ी, जब आतंकवादी हमले हो रहे थे देश पे और आतंकवाद देश में घुसने का प्रयत्न कर रहे थे तब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उन्होंने देश का सम्मान और गौरव और सुरक्षा के कारण, बिना प्राण की चिंता करे, सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे आतंकवादी पडोसी को चेतावनी भी दी और समझा दिया कि देश की सुरक्षा और एकता के कारण हमारे सेनानी कभी पीछे नहीं हटेंगे | यह देश

अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जनता है और ख़ुशी की बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक में हमारा एक भी सेनानी का जीवन उन्हें बलिदान नहीं करना पड़ा और बहुत ही सफलता के साथ हमने अपने पडोसी देश को सर्जिकल स्ट्राइक के दौरा एक सबक सिखाया |

मैं आज आते वक़्त पढ़ रहा था देवभूमि उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार का दृष्टिकोण है आगे, कैसे विकास से हम इस प्रदेश का पूरा चित्र ही बदलना चाहते हैं | और बड़ा आनंद आया कि अलग अलग वर्गों के लिए कई विषयों पे विशेष ध्यान दिया गया है फिर चाहे वह शिक्षा को बहतर करने का विषय हो, स्वास्थय सेवाओं में हर व्यक्ति को कैसे अच्छी स्वास्थय सेवाएं मिलें | पर्यटन और तीर्थ स्थानों पे सुविधाजनक, लोगों को जाने की सुविधाएं बढें उसके लिए कैसे उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की आगे आने वाली पूर्ण बहुमत की सरकार प्रयत्न करेगी और successfully पर्यटन को बहुत गति देगी उत्तराखंड में | कृषि के विषय में खासतौर पे बहुत सारी योजनाओं के बारे में लिखा गया है, छोटे सीमान्त किसानों के फसली ऋण को माफ़ किया जायेगा, बिना ब्याज के उनको ऋण दिया जायेगा |

मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा आज आप सबके समक्ष, हमारे उत्तराखंड के जो किसान महनत करके अपना उत्पादन करते हैं, उन सभी किसानों को जिनके पास बाबा आदम के ज़माने के पुराने पंप चल रहे हैं उनको हम मुफ्त energy efficient pump देके उनकी सुविधा भी बढ़ाएंगे, बिजली की जो खपत है उसको भी कम करेंगे जिससे उनके बिजली में राहत मिले, बिजली के बिलों में और फ्लो मीटर होगा हर पंप में जिससे उनको अनुमान हो जायेगा कितना पानी चाहिए उतना पानी देंगे, ज्यादा पानी भी हमारी soil को ख़राब करता है, किसानों की ज़मीन को ख़राब करता है | हर एक को Soil Card दिया जायेगा जिसके हिसाब

से वह तय कर सके कितने पानी की आवश्यकता है, कितनी खाद की आवश्यकता है | गत दो वर्षों में हर एक किसान को पर्याप्त खाद मिला है और सस्ता खाद मिला है, खाद की कीमतें भी कम हुई हैं | और इस energy efficient पंप में किसान अपने घर बैठे SMS द्वारा पंप चालू भी कर पायेगा, flow meter से देख पायेगा कि पानी पर्याप्त पहुँच गया और SMS द्वारा पंप बंद भी कर पायेगा, ऐसा एक मुफ्त पंप उत्तराखंड की सरकार हर पुराने पंप को replace करके उत्तराखंड के किसानों को देगी | युवाओं को पढने के अच्छे अवसर, खासतौर पे कन्याओं को, हमारी छोटी बहनों को BA तक, graduation तक मुफ्त शिक्षा के अवसर प्रदान किये जायेंगे, बुनयादी विकास को और मज़बूत और तेज़ी से बढाया जायेगा | और कैसे इस प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास का हमारा जो मूलभूत योजना है सोच है, उसके तहत समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र को कैसे विकास से जोड़ना, तेज़ी से जोड़ना उसके प्रति हमारी सरकार और हमारे सभी नेता दिन और रात प्रयत्न करके उत्तराखंड को विकास की नयी ऊँचाइयों तक पहुँचायेगे, यह विश्वास उत्तराखंड की जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, हम सब केंद्र के उनके सहयोगी और आगे आने वाले उत्तराखंड के हमारे नए विधायक और नया नेतृत्व प्रयत्नशील रहेगा यह विश्वास आपके माध्यम से मैं उत्तराखंड के जनता को देना चाहूँगा |

बहुत बहुत धन्यवाद |

Q&A

Q. पियूष जी, सर एक सवाल है आपने भ्रष्टाचार की बात की, बिजली में भ्रष्टाचार की बात की, 56 power project निशंक जी के टाइम पे release हुए थे उसके बाद उन्होंने roll-back करके वापिस ले लिया था | उस वक़्त एक बड़े भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, इस वक़्त का भ्रष्टाचार कौन सा है ऊर्जा को लेके?

A. कांग्रेस की सरकार पांच वर्ष रही तो अगर कुछ उस समय गलत काम हुआ होता तो मैं समझता हूँ पांच वर्ष पर्याप्त समय है वह उसके बारे में जांच की होगी और निशंक जी ने बेदाग़ सरकार चलाई थी, उस समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं था | फिर भी यह संवेदनाशील भारतीय जनता पार्टी है जिसने तुरंत उसपे एक्शन लेके उसको स्थगित भी किया कि उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई आरोप न लग सके | हमने जब देखा यहाँ के काम को, उत्तराखंड के तो तब पाया कि किस प्रकार से जो केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं के द्वारा यहाँ पे पैसे आवंटित करती है उसमें क्वालिटी क्यों ख़राब होती है, tendering process में किस प्रकार की गडबडें होती हैं और क्योंकि यहाँ की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई, tendering process को लेके सवाल उठे | तो मैंने यह विषय रखा कि इसकी जांच की जाएगी और जो केंद्र से पैसा आता है वह सदुपयोग हो उसको सुनिश्चित किया जाये |

Q. आप यह कह रहे हैं कि प्रोसेस जो ख़राब हुए हैं, पॉवर सेक्टर में तमाम गड़बड़ियाँ रही है लेकिन पिछले दो साल में central government का जो power की ही एक agency rating करती है सारे DISCOMS की पूरे देश भर में, तो उस्सी एजेंसी ने लगातार दो साल से उत्तराखंड के पॉवर कारपोरेशन को 27वें नंबर से 30वे नंबर पे ले आये हैं आप?

A. देखिये यही तो इस भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और यह सिद्द करता है कि हम अभी कोई भेदभाव नहीं करते हैं | जो जो लोग सुधार करेंगे तो हम उसका reporting proper करते हैं | आपको याद होगा कांग्रेस के समय जब गुजरात प्रथम श्रेणी में आया था और 5-6 award गुजरात की सरकार को मिलने जा रहे थे तो उस समय के ऊर्जा मंत्री ने program cancel कर दिया लेकिन गुजरात को जो प्रथम श्रेणी आया था उसको award देने से इनकार कर दिया | लेकिन भ्रष्टाचार अलग विषय है अगर यहाँ पे हमने जैसे बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध

करवाई केंद्र से, हमने पैसा दिया उसके कारण यहाँ पे अगर सबको बिजली चौबीस घंटे दे सकती है सरकार तो उसका श्रेय तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है | और उससे ही यहाँ पे जो श्रेणी सुधरी उत्तराखंड की हमने उसको आपके समक्ष रखा तो हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया | मैंने जब कोयले का भी आवंटन किया कोयले के blocks, तब महाराष्ट्र में स्थित कोयले के blocks जो महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार थी उसको भी हमने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को दिया | तो हमने कभी भेदभाव नहीं किया है | जब LPG connection देने की बात आई तब उत्तराखंड में हर गरीब के घर में LPG connection दिए गए, केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त connection दिए गए तो हर प्रकार से केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के उत्तराखंड को सहयोग किया है |

Q. आपने बताया दो साल से अधिक हो गया आपको मंत्री पद सँभालते हुए, उत्तराखंड प्रदेश के लिए आपने कुछ मुहय्या कराया हो .. यह बता दीजिये?

A. हमने लगभग 17% अधिक बिजली दी है राज्य सरकार को इस दौरान, हमने power exchange में बिजली इतनी सस्ती कर दी कि उसके कारण ही कल वह 411 MW बिजली खरीद पाए | हमने उत्तराखंड में जो power supply का अगर आंकड़ा चाहिए तो लगभग 804 million unit अधिक उपलब्ध कराया है केंद्र सरकार द्वारा 2015-16 में, 2014 के निस्बत जिसके कारण यहाँ पे बिजली की स्थिति सुधर पाई और आज energy shortage .5% पे ला पाए | अलग अलग schemes के द्वारा, Power System Development Fund के द्वारा लगभग 125 करोड़ रुपये उत्तराखंड को 17 March, 2016 को दिए गए | दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत नए project sanction किये गए लगभग 788 करोड़ रुपये के, साथ ही साथ IPDS, Integrated Power Development Scheme के अंतर्गत लगभग एक सौ, नहीं, ज्यादा है, Integrated Power Development

Scheme के तहत यहाँ पे उत्तराखंड को 191.63 करोड़ रुपये sanction किये गए, Rs 203.59 crore sanction किये गए schemes के लिए | तो अन्य अन्य योजनाओं से उत्तराखंड को लाभान्वित किया गया है |

Q. अभी वर्तमान में यह जो 37 million unit की खपत राज्य को है, जैसे आज की ही बात की जाये तो 37 million unit है | राज्य इसमें से मात्र 14 million unit खुद से ले रहा है बाकी यह बाहर से या सरकार से ले रहा है | आपने अपने manifesto में चौबीसों घंटे बिजली देने के लिए बोला गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 24 प्रस्तावित यूनिट पे stay लगा दिया है | आप इसको कैसे पूरा करेंगे, आपका क्या vision है?

A. सुप्रीम कोर्ट में जो stay है उसको तो हमने कोर्ट के माध्यम से ही clear करवाना पड़ेगा लेकिन वह सिर्फ Ganga Basin के projects का है, अलकनंदा और भागीरथी के लिए | मुझे लगता है कि उत्तराखंड में और कई योजनाओं को चालू किया जा सकता है, run of the river projects की यहाँ पे पर्याप्त संभावना है और भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रस्तावित किया है कि run of the river projects को जिससे अविरल नदियों में भी कोई नुक्सान नहीं होता है उसको और तेज़ गति से लागू किया जाये | उत्तराखंड में हाइड्रो की संभावनाएं ज्यादा हैं, 12% मुफ्त बिजली राज्य को मिलती है, 1% उस क्षेत्र को मिलती है उसके बावजूद इतने वर्षों में मात्र 2000 MW उत्तर प्रदेश में अभी तक स्थापित किये गए हैं |

Q. आपने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन और पॉवर के क्षेत्र में अपार संभावना है तो उनको कैसे harness करेंगे जब already आपने एक Eco-sensitive zone बना है जिसकी वजह से जहाँ पे वह river का है, जहाँ पे वह बनाया जा सकता है वहां तो already ban करा हुआ है तो कैसे संभव है?

A. जहाँ पे Eco-sensitive zone है मुझे लगता है आप भी agree करेंगे कि आप उत्तराखंड की eco-sensitivity को damage नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पूरा उत्तराखंड कोई Eco-sensitive zone नहीं है और भी कई संभावनाएं हैं जिसमें, जैसा मैंने पहले भी कहा run of the river projects हैं, कुछ existing schemes की capacity expansion की संभावना है | मैं समझता हूँ कि mind अगर open रखेंगे तो संभावनाएं भी सामने आएँगी | दुर्भाग्य से कोई भी नयी प्रोजेक्ट मेरे सामने यहाँ से प्रस्तावित नहीं किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी हम अपना पक्ष रख रहे हैं कि कैसे इसको review करके इस Eco-sensitive zone को भी review किया जाये और कैसे उत्तराखंड के hydro potential को और तेज़ी से harness किया जाये |

Q. सर आपने यह जो पंप की बात की है, यह पंप सिर्फ उत्तराखंड में बदले जायेंगे या पूरे भारत में?

A. यह हर राज्य के हाथ में है, आंध्र प्रदेश ने agree किया है केंद्र सरकार के साथ तो हम आंध्र प्रदेश में लागू कर रहे हैं | अब मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमारी सरकार भाजपा की बनेगी इन दोनों जगह लागू करने जा रहा हूँ |

Q. और दूसरा सिर्फ गरीब लोगों के बदले जायेंगे या जो अमीर लोग हैं उनके भी?

A. हर एक किसान जिसका पंप 10 वर्ष से पुराना है उन सभी किसानों के पंप energy efficient नए पंप के माध्यम से बदले जायेंगे, मुफ्त में |

Q. आपने surgical strike की बात करी, surgical strike जब हुआ था तो हमने कितने वहां के जो पाकिस्तान में जो हम border हम cross करके गए थे वह कितने सैनिकों को हमने वहां पे मारा और उसके बाद से हमारे कितने यहाँ हमारे

borders पे strike हुए और उसमें हमारे कितने सैनिक या वहां के नागरिक शहीद हुए?

A. दुर्भाग्य की बात है कि आप आंकड़े पूछ रहे हो जो आंकड़े कोई आर्मी के अलावा और कोई नहीं दे सकता है |

Q. सर आपने कहा कि निशंक जी की सरकार जब यहाँ आई थी तो उनको तीन महीनों में क्यों हटाया गया और क्या आप यहाँ की जनता को बता सकते हैं या फिर प्रेस को बता सकते है कि अभी पांच साल का कोई मुख्यमंत्री..... क्योंकि आपने कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाई है?

A. हमारे पास उत्तराखंड में अच्छे नेता हैं, विधायक जल्द अपने नेता का चयन करेगा और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमारे पास अच्छा शीश नेतृत्व है जो इस प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से विकास और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे सकता है | हमने कोई एक particular नाम नहीं अभी तक घोषित किया है विधायक दल इसको तय करेगी |

Q. मैंने Europe में देखा है कि hills में जो है windmill का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे आजतक जो है windmill के लिस्ट में कुछ नहीं किया गया, सेंटर को प्लान करके यहाँ पे .....?

A. मैं आपको बताऊँ windmill की संभावनाएं भी हो सकती हैं, solar, सौर ऊर्जा की भी संभावनाएं भी हो सकती हैं, hydro में तो बहुत potential है उस सबके बावजूद, आजके दिन जो परिस्थिति है मात्र 326 MW renewable energy उत्तराखंड में बनाई जा रही है, मात्र 326 | तो मैं समझता हूँ कि नयी सरकार ने इसके ऊपर नयी तरीके से सोचना पड़ेगा | Wind की मेरे पास यहाँ पे specific कितनी संभावना है वह आंकड़े नहीं है आप चाहे तो वह भी मैं आपको भेज सकता

हूँ पर आज के दिन जितनी संभावनाएं हैं उतनी संभावनाएं दुर्भाग्य से इस प्रदेश में पूरी तरीके से exploit नहीं की गयी है |

Q. सर आप यह जो उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण हाइड्रो प्रोजेक्ट है .... उसमें जो पैसा केंद्र ने उपलब्ध किय था वह जारी नहीं किया गया है इसलिए वह जो महत्पूर्ण परियोजना जो है वह सही तरह से run नहीं कर पा रही है | दूसरा सवाल मेरा यह है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो hydro projects हैं उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो विद्युत् क्षेत्र में उत्पादन के श्रेणी उतरी है, यह कैसे मुमकिन है? या तो राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया.....

A. मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पर्याप्त, मैंने अभी आपको बताया पढके बताया मोबाइल अप्प से, वह अप्प आप लोग भी डाउनलोड करलें तो आपको दिनों-दिन खबर मिलती रहेगी - विद्युत् प्रवाह | हमें यह सुनिश्चित किया, कहाँ एक ज़माने में बिजली पॉवर एक्सचेंज में 8 और 10 रुपये यूनिट बिकती थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिजली का उत्पादन, कोयले का उत्पादन इतना बढाया कि आज पूरे देश में किधर भी बिजली की कमी नहीं है, कोयले की कमी नहीं है जिससे बिजली के दाम इतने कम हो गए हैं कि उत्तराखंड की सरकार को पर्याप्त मात्र में एक्सचेंज से बिजली खरीदने को मिली | परन्तु मैं समझता हूँ एक अच्छे राज्य को बिजली में, विद्युत् में सुरक्षा भी होनी चाहिए तो वह अगर अपनी सुरक्षा चाहें तो उन्होंने बड़े रूप में या अपनी परियोजनाएं बनानी चाहिए उसमें 12% मुफ्त बिजली मिलेगी तो उनके खर्चा करके बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी, मुफ्त बिजली से इस देश की जनता की सेवा कर पाएंगे | उसकी जानकारियां मैं निकाल के आपको दे दूंगा |

Q. बीजेपी जो है वह सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर उत्तराखंड में वोट मांग रही है आपने भी कहा कि.....

A. मैंने उसको मेरे बड़े लम्बे उसमें एक विषय रखा, तो उसके नाम पे हम कोई वोट नहीं मांग रहे हैं, मैं आपको इससे correct कर रहा हूँ कि हम उसके नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं | हमने सिर्फ जानकारी दी |

Q. सवाल सुन लीजिये, आपने कहा कि बधाई हो उन सैनिकों को जो वहां पे जा करके उन्होंने ऑपरेशन अंजाम दे दिया और एक भी जवान जो है शहीद नहीं हुआ | लेकिन 28 सितम्बर को यह कार्रवाई होती है और आजतक क्या आपके पास या केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा खाता है कि कितने जवान हमारे मारे गए हैं, उत्तराखंड के कितने जवान अबतक मारे गए हैं, इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कितने जवान जो हैं वह शहीद हुए हैं?

A. चलिए और कोई है, इसका जवाब मैं दे चूका हूँ |

Q. What is your stand on stalled power projects?

A. Our stand is very clear. कि गंगा अविरल रहनी चाहिए और उसकी अविरलता को रखते हुए जो जो प्रोजेक्ट्स हम शुरू कर सकते हैं उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में request करेंगे एक final निर्णय के लिए | आज के दिन वह sub judice है लेकिन हम साथ ही साथ गंगा को अविरलता को भी ख़राब नहीं होने देना चाहते |